अप्रैल 2022 ₹ 20

समाजवादी बुलेटिन

भाजपा सत्ता में आई बढ़ चली

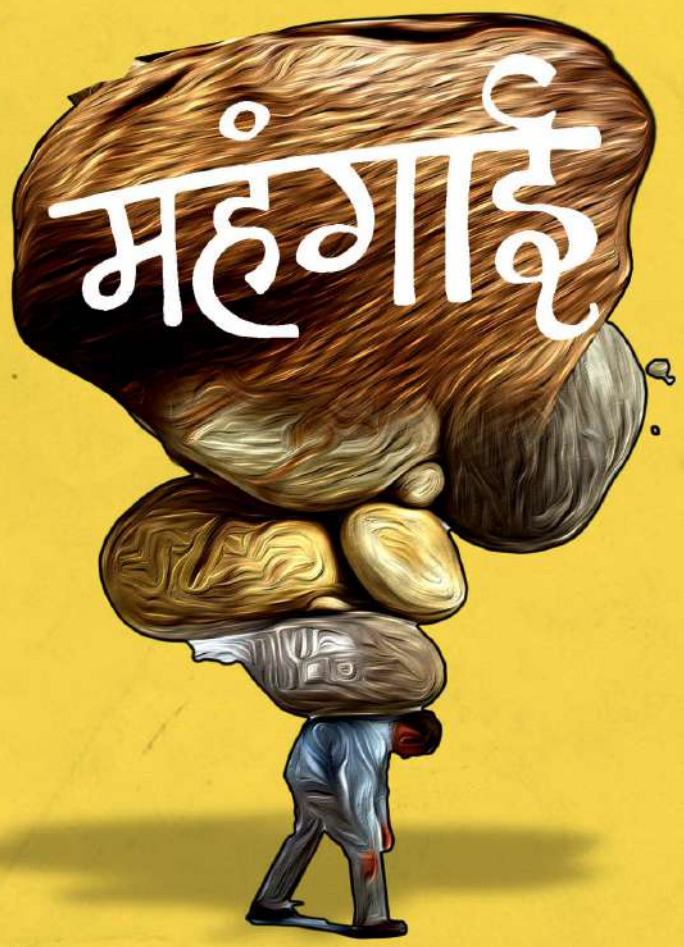

R.N.I. No. 68832/97

सांप्रदायिक ताकतें माहौल खराब कर चुनावी लाभ लेने की कोशिश में लगी रहती हैं। समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि वे जनता को साथ लेकर इन ताकतों के मंसूबों को नाकाम करें। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का पूरा प्रयास किया है और आगे भी करती रहेगी। गांधी ने हमें जो रास्ता दिखाया है वही देश के लिए सही रास्ता है।

मुलायम सिंह यादव
संस्थापक-संरक्षक, समाजवादी पार्टी

समाजवादी बुलेटिन

अप्रैल 2022
वर्ष 23 | संख्या 06

प्रिय पाठकों,
आपकी प्रिय पत्रिका समाजवादी बुलेटिन बदले हुए कलेवर में अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। आपके उत्साहवर्धन और प्रेम के कारण ही हमारा यह सफर यहां तक पहुंचा है। हम भरोसा दिलाते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की अपनी कोशिशों में कोई कमी नहीं आने देंगे। कृपया हमेशा की तरह आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहें।
धन्यवाद!

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक
प्रोफेसर रामगोपाल यादव
☎ 0522 - 2235454
samajwadibulletin19@gmail.com
bulletinsamajwadi@gmail.com
Mob:- 9598909095
/samajwadiparty

समाजवादी पार्टी के लिए
19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित
अवध पब्लिशिंग हाउस, 8 पान दरीबा, लखनऊ से मुद्रित

R.N.I. No. 68832/97

अंदर

आजम साहब : संघर्ष और हौसले की मिसाल 04

10 कवर स्टोरी

बढ़ चली महंगाई

फोटो स्रोत : गूगल

कानून व्यवस्था ठप 06

उत्तर प्रदेश में भाजपा की दूसरी पारी में भी प्रदेश को अपराध प्रदेश बनाने की प्रक्रिया चालू है। भाजपा उत्तर प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था को इसीलिए बढ़ावा देती है ताकि लोग असुरक्षा में तनावपूर्ण जिंदगी जीने को बाध्य हों।

अंबेडकर जयंती: झिलमिलाए स्मृति दीप 24
समाजवादियों से ही है न्याय की आस 34

आजम साहब

संघर्ष और हौसले की शानदार मिसाल

फाइल फोटो

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में शामिल पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान साहब हौसले और संघर्ष की शानदार मिसाल हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने बीते 2 साल से आजम साहब को तमाम झूठे मुकदमों में फंसा कर प्रताड़ित करने जो कोशिश की है उसने आजम साहब जैसी शख्सियत का हौसला बिल्कुल कमजोर नहीं किया है।

समाजवादी विचारधारा और जनता को सबसे बड़ा निर्णायक मारने वाले आजम साहब संघर्ष की इस घड़ी में भी समाजवादी सिद्धांतों के प्रमुख झंडाबरदार के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि सत्तारूढ़ खेमा आजम साहब की लोकप्रियता

और मजबूत जनाधार के खौफ के कारण ही उन्हें सलाखों के पीछे रखने की साजिशें कर रहा है लेकिन अदालत ने अधिकांश मामलों में आजम साहब को जमानत दे दी है और समाजवादी परिवार को अदालत पर पूरा भरोसा है और यह विश्वास कि बाकी मामले में भी उन्हें जल्द ही जमानत मिल जाएगी और जनता का नायक फिर एक बार जनता के बीच ही होगा।

जनता के बीच आजम साहब की लोकप्रियता और मजबूत जनाधार कां संकेत इससे ही मिलता है कि लंबे समय से जनता के बीच ना होने के बावजूद रामपुर से विधानसभा के चुनाव में उन्होंने विपक्षी भारतीय जनता पाटी को भारी मतों से हराया और रामपुर से विधायक चुने गए। भाजपा सरकार का उत्पीड़न भरा रवैया और साजिशें नाकाम रहीं। रामपुर की जनता ने आजम साहब को विधानसभा में अपना प्रतिनिधि चुनकर भेज दिया।

चूंकि भाजपा सरकार ने आजम साहब पर गलत मुकदमे लाद कर उन्हें कैद कर रखा है लिहाजा रामपुर की जनता ने खुद ही आजम साहब का चुनाव लड़ा और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाया। सत्ता की साजिशों को नाकाम कर आजम साहब जनता की कसौटी पर खरे उतरे। खास बात यह है कि भाजपा ने जिस व्यक्ति को मोहरा बनाकर आजम साहब के खिलाफ फर्जी मुकदमे लगवाए हैं, चुनावों में आजम साहब ने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर लड़ रहे उसी शख्स को जनता के आशीर्वाद से धूल चटा दी।

इन चुनावों में फिर एक बार साबित किया है सत्ता और सरकार चाहे लाख साजिशें करें जनता की अदालत में आजम साहब बेदाग थे, बेदाग हैं और आगे भी बेदाग रहेंगे।

आजम साहब दसवीं बार रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चुने गए हैं। इससे भी साबित होता है रामपुर की जनता उन्हें अपना कितना प्यार और समर्थन देती रही है।

चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने भी आजम साहब के समर्थन में रामपुर में चुनाव प्रचार किया।आजम साहब की अनुपस्थिति के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता क्षेत्र में मजबूती से प्रचार करते रहे।

उन्होंने जनता को बताया कि कैसे झूठे मामलों में फंसाकर आजम साहब और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान किया जा रहा है।

इलाकाई लोगों का कहना है कि आजम साहब की चुनाव मैदान में अनुपस्थिति भले रही लेकिन उससे खास फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि जनता ही उनका चुनाव लड़ती रही। जनता खुद ही बता रही थी और याद कर रही थी कि आजम साहब ने रामपुर के लिए कितना कुछ किया है। लिहाजा इस बार वोट की चोट कर उनसे हुए अन्याय के खिलाफ जनता ने अपना विरोध दर्ज कराया है।

रामपुर का जनादेश बता रहा है कि एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार के प्रति सियासी बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई कतई बर्दाश्त नहीं जा सकती। लोगों ने सरकार की मनमानी का जवाब चुनावों में वोट के जरिए दिया है।उल्लेखनीय है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव कई मौकों पर कह चुके हैं कि आजम खान साहब के साथ जो व्यवहार भाजपा सरकार कर रही है वह अनैतिक एवं अमानवीय है। लोकतंत्र में सरकार का आचरण बिना राग द्वेष का होना चाहिए। भाजपा सरकार द्वारा समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपमानित करने और यातना देने के लिए झूठे केसों में फंसाया जाता रहा है। भाजपा समझती है कि इससे समाजवादी पार्टी का मनोबल तोड़ा जा सकता है। भाजपा इसमें कभी सफल नहीं हो सकेगी।

आजम साहब वह शख्सियत हैं जिन्होंने आपातकाल में दो वर्ष तक जेल की यातना सही। वे 9 बार विधायक, 5 बार मंत्री और एक बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। रामपुर से दसवीं बार विधायक चुने जाने से पहले वह रामपुर से लोकसभा के सदस्य रहे हैं। उन्होंने तालीम के क्षेत्र में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर में स्थापित कर ऐतिहासिक काम किया। शासन-प्रशासन की हरकतों से आजम साहब का वह शानदार इतिहास नहीं धुल जाएगा जिसमें वे गए कई दशकों से रामपुर और आस-पास की राजनीति का चेहरा बदल देने वाले नायक के तौर पर नजर आते हैं।

गाजियाबाद में दो युवकों की गोली मारकर हत्या

दुस्साहस

गाजियाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। थाना कविनगर के वेब सिटी सेक्टर-4 के गेट के पास अज्ञात बदमाशों ने दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद बदमाश फरार हो गए।

वेब सिटी के गार्ड ने 112 के माध्यम से पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना के बाद एसएसपी समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी मुनिराज जी ने बताया कि रात करीब 9:30 बजे वेवसिटी सेक्टर-

- वेब गेट
- शव पर

4 के गार्ड सूचना दी के पास दी। बाद पुलिस को गोली चुकी थी। पर मिले हुई। दोनों गया है। मृ मदन निवासी उर्फ चेतन पुत्र बिसंबर के रूप में हुई है।

यूपी तक ताज़ा ख़बर UP Tak

लखीमपुर सदर सीट से बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक सवार चाचा भतीजे को रौंदा, मौत

www.uptak.in

'बाबा' का बुलडोजर चोरी!

- एफआईआर दर्ज कर पुलिस कर रही है तलाश
- चेकिंग के दौरान सीज कर लाया गया था थाने

बाबा का बुलडोजर

दोनों आरोपी मौके से फरार

LIVE AKING NEWS

एबीपी गंगा संवाददाता को धमकाने में जुटे पुलिस अधिक

गुस्साए परिजनों ने NH-58 पर लगाया जाम

प्रयागराज में फिर सामूहिक हत्या: एक परिवार के 5 का गला रेता, 4 की मौत, शवों को जलाने के लिए घर में लगा दी आग

पोते को लेने स्कूल जा रही महिला से कुंडल लूट

मेरठ। शास्त्रीनगर बाइक सवार बदमाश ने महिला का कुंडल लूट लिया। महिला को लहूलुहान देख लोग एकत्र हो गए और उपचार दिलाकर घर भिजवाया।

मोदी रबड़ से रिटायर्ड शौकेंद्र पाल सिंह जागृति विहार सेक्टर दो में रहते हैं। बुधवार दोपहर उनकी पत्नी पुष्पा पोते को लेने स्कूल जा रही थीं। शास्त्रीनगर बी-ब्लॉक पार करते ही पीछे से आये बाइक सवार बदमाश झपट्टा मारकर कुंडल लूटकर फरार हो गए। लोगों

- लहूलुहान हुआ कान लगवाने पड़े टांके
- मेडिकल थाना क्षेत्र के बी-ब्लॉक से जुड़ा मामल

लोग भी पहुंच गए। जब लोगों ने म से थाने जाकर शिकायत करने क कही तो उन्होंने मनाकर दिया। कहना था

बंधक बनाकर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म

इलाके की घटना, तीन पर मुकदमा दर्ज, सभी फ

सुबह घर से निकली किशोरी को छत पर ले जाकर

घरवालों ने पहले राड बनाया

नदहाड़े तमंचे के बल पर छात्रा को लूटा

CRIME

बाराबंकी: बीजेपी का झंडा लगी एसयूवी में मिला गला कटा शव, जांच में जुटी पुलिस

आगरा: हिरासत में किशोर की हालत बिगड़ी, परिजनों ने पुलिस पर लगाया पिटाई का आरोप, थाने में हंगामा

संवाद न्यूज एजेंसी, आ

मुकेश कुमार Updated

PM IST

सरेराह महिला से छेड़छाड़, तेजाब डालने की धमकी दी

नौचंदी थाना क्षेत्र का मामला, मोहल्ले का युवक कर रहा

कैश और मोबाइल दो वरना तेजाब से नहला दूंगा

SHOCKING

अमर उजाला शहर चुनें

होम › उत्तर प्रदेश › गोरखपुर लखन

Hindi News › Uttar Pradesh › Gorakhpu

गोरखपुर में हैवानियत: बंधक बनाकर किशोरी से किया सामूहिक दुष्कर्म, छत पर ले जाकर की गई वारदात

उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by:

यूपी का हाल
कानून व्यवस्था
ठप

बुलेटिन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में भाजपा की दूसरी पारी में भी प्रदेश को अपराध प्रदेश बनाने की प्रक्रिया चालू है। भाजपा उत्तर प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था को इसीलिए बढ़ावा देती है ताकि लोग असुरक्षा में तनावपूर्ण जिंदगी जीने को बाध्य हों।

भाजपा राज में न कानून का डर, न पुलिस का खौफ, उत्तर प्रदेश में है सिर्फ जंगलराज। जिस सरकार में बैंक तक सुरक्षित नहीं वहां आम आदमी की सुरक्षा का प्रश्न ही बेमानी है। भाजपा जिस तरह प्रशासन को पंगु बना रही है उससे सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है? प्रदेश में बढ़ रही अराजकता के लिए भाजपा अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। जनता के समक्ष उसको जवाबदेही देनी होगी।

भाजपा ने अपने कारनामों से उत्तर प्रदेश को बदनाम किया है। भाजपा लोगों में भय पैदा

करके राज कर रही है। यह लोकतंत्र में घोर निंदनीय है। युवा आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबाने के लिए पुलिस की लाठियां चटकने लगती है।

उत्तर प्रदेश में भाजपा के दूसरे कार्यकाल में अपराधी पहले से ज्यादा निडर हैं, उन्हें पुलिस का तनिक भी खौफ नहीं रह गया है। बैंक लूट, लॉकर चोरी, बलात्कार, गोलीकांड और हत्या की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रदेशवासी आतंकित है। चारों तरफ भय का वातावरण है। उत्तर प्रदेश में अपराध की बुलेट ट्रेन दौड़ रही है।

रायबरेली में प्रधान के भाई की हत्या हुई जब रात में खेत की रखवाली करने गया था। सीतापुर के बिसवां के एक गांव में घंटो तक अपराधियों ने तांडव मचाया। हैदरगंज थाना क्षेत्र में लुटेरों ने सिपाही से रायफल और बाइक लूट ली। बदायूं में थाने के सामने व्यापारी की हत्या हुई। बलिया में प्रापर्टी डीलर की गला काटकर हत्या कर दी गई। गोरखपुर में बासगांव थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव में छः वर्षीय मासूम का शव बरामद हुआ।

मिशन शक्ति अभियान के तहत एंटी रोमियो दल की कवायद कागजी साबित हुई है। मेरठ में कई छात्राएं छेड़छाड़ की शिकार बनीं। नोएडा में छेड़खानी की शिकायत पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न होने से परेशान पीड़िता ने आत्मदाह कर जान दे दी। राजधानी लखनऊ में घर में घुसकर शिक्षका से छेड़छाड़ की गई और उस पर तेजाब फेंकने की धमकी दी गई। पुलिस के अन्याय के चलते लाचारी में बेटियों द्वारा मौत को गले लगाने की घटनाएं भाजपा राज पर कलंक है।

भाजपा सरकार में कानून-व्यवस्था बदहाल है। मुख्यमंत्री जी दावे तो बड़े-बड़े करते हैं परन्तु सच्चाई यह है कि प्रशासन तंत्र पर उनका नियंत्रण ही नहीं रह गया है। एक तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का शून्यकाल चल रहा है। उत्तर प्रदेश अराजकता की गिरफ्त में है। गत पांच वर्षों से यही स्थिति बनी हुई है।

पूरे दिन मुख्यमंत्री बुलडोजर का स्टेयरिंग लिए विपक्षियों के पीछे घूम रहे हैं जबकि सत्ता संरक्षित अपराधी कहर बरपा रहे हैं। मुख्यमंत्री का कथित जीरो टॉलरेंस का दावा लोकभवन के अंदर या मुख्यमंत्री आवास तक ही सीमित नज़र आता है। अपराधी तत्व बेफिक्र होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।

मिशन शक्ति अभियान के तहत एंटी रोमियो दल की कवायद कागजी साबित हुई है। मेरठ में कई छात्राएं छेड़छाड़ की शिकार बनीं। नोएडा में छेड़खानी की शिकायत पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न होने से परेशान पीड़िता ने आत्मदाह कर जान दे दी

पूरे प्रदेश में जंगल राज नज़र आता है।

फिरोजाबाद में बेखौफ बदमाश सर्राफ को गोली मारकर जेवरों से भरा बैग लूट ले गए। संत कबीरनगर में अपहरण कर बालक की हत्या कर दी गई। प्रतापगढ़ के जेठवारा क्षेत्र के नारायनपुर में भी एक सर्राफा व्यापारी को लूट के बाद गोली मारकर बदमाश भाग गए। प्रयागराज में नवाबगंज में राहुल तिवारी के परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या हुई। गोरखपुर में ऑटो से जा रही महिला का गुलरिहा थाना क्षेत्र में मंगलसूत्र छीन लिया गया। बांदा में सत्ता संरक्षित गुंडों द्वारा अतुल गुप्ता की पिटाई के बाद हत्या कर दी गई। शाहजहांपुर में भाजपा नेता द्वारा युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है।

प्रदेश में कारोबारियों की जिंदगी खतरे में है। 15 दिन में 6 कारोबारियों से लूट हो गई। बरेली के कपड़ा व्यवसायी से बदायूं में दिन दहाड़े लूट हुई। महोबा जिले के अजनर थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ हैवानियत की हद हो गई।

उत्तर प्रदेश में अन्याय-अत्याचार से बहू-बेटियां बुरी तरह परेशान है। राजधानी लखनऊ में ढाई महीने में 25 चेनें लूटी गई हैं। लखनऊ में पुलिस वाले ही लूट में शामिल पाए गए। कुंडा में रेप की रिपोर्ट दर्ज कराने 17 किलोमीटर पैदल चलकर पीड़िता पहुंची पर जांच के नाम पर पुलिस टालमटोल करती रही। समाजवादी सरकार के समय यूपी डायल 100 नम्बर सेवा शुरू की गई थी ताकि चंद मिनटों में पुलिस घटना स्थल पर पहुंच सके। भाजपा सरकार ने 100 नम्बर बदलकर 112 कर दिया और उसको सक्रिय बनाने के बजाय निष्क्रिय कर दिया।

उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था को देखते हुए आखिर कौन निवेश के लिए आगे

भाजपा राज में यूपी बना अपराध प्रदेश

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में क्राइम ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का जीरो टॉलरेंस एक बड़े जीरो में बदल कर रह गया है। भाजपा राज में उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन गया है।

माफिया, पुलिस और शासन की मिलीभगत से समस्त न्यायिक और संवैधानिक मर्यादाएं टूट कर छिन्न भिन्न हो रही हैं। लोगों में दहशत है। प्रदेश में भय और असुरक्षा का वातावरण है।

बेटियों के रात 12 बजे भी गहने पहनकर सुरक्षित बाहर निकलने का दावा करने वाले सत्ताधीशों के राज में बेटियों का जीना दुश्वार हो गया है। मेरठ में घर से बाहर तक मनचले बहन बेटियों, महिलाओं को परेशान करते रहे, मुख्यमंत्री जी का ऐंटी रोमियो स्क्वाड कहीं दिखाई नहीं पड़ा। अकेले लाल कुर्ती क्षेत्र में छेड़छाड़ की पांच घटनाएं घटीं। गोमतीनगर लखनऊ में भाई के सामने बहन से छेड़छाड़ की गई। वाराणसी में 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। फूलपुर प्रयागराज में ठोकरी गांव में दादी-पोते की हत्या कर दी गई।

जिन पर जनता को भयमुक्त करने की जिम्मेदारी है, वही जब रक्षक की जगह भक्षक की भूमिका में दिखे तो जनता कहां न्याय की गुहार करे? बरेली में एक सिपाही ने एक युवती की मोबाइल और स्कूटी तोड़ दी। खागा फतेहपुर में लड़की का पिता तीन माह से नाबालिग बेटी की बरामदगी के लिए अधिकारियों के चक्कर काटता रहा लेकिन पुलिस ने बरामदगी तो दूर मामले की जांच भी करना मुनासिब नहीं समझा।

सच तो यह है कि भाजपा सरकार के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद प्रदेश में अपराधों में बाढ़ आ गयी है। जनता की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। सत्ता के मद में भाजपा इतना चूर हो गई है कि उसे अब कायदे कानून या संविधान की कोई परवाह नहीं रह गई है।

आएगा? ऐसा लगता है भाजपा सरकार का इरादा प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का नहीं, प्रदेश के गौरव को धूल धूसरित कर देने का है।

भाजपाइयों द्वारा सत्ता के डबल इंजन की पावर वाली गाड़ी से लोगों को रौंदने का सिलसिला भी बेरोकटोक चल रहा है। भाजपाई विधायक की गाड़ी से लखीमपुर खीरी में कुचलकर 2 भाइयों की मौत हो गई। राजधानी लखनऊ में बदमाशों ने तांडव किया। 20 बदमाशों ने मिलकर 5 थाना क्षेत्रों में उत्पात मचाया, कार सवारों पर बमबाजी और फायरिंग की। पुलिस-प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा।

लोकतंत्र की बड़ी-बड़ी बातें करने वाले भाजपाइयों के राज में पत्रकार सर्वाधिक उत्पीड़न के शिकार हो रहे हैं। अयोध्या के बीकापुर में सत्ता संरक्षित दबंगों द्वारा पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया। बलिया में पत्रकारों की गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। झांसी में भी पत्रकार पर हमला बोला गया।

भाजपा राज में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर निर्मम प्रहार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधी बेलगाम हो रहे है। भाजपा सरकार में न्याय नहीं, हर तरफ शासन सत्ता की मनमानी चल रही है। निर्दोष पिस रहे हैं और गरीब की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है यही भाजपा राज की सच्चाई है।

भाजपा सत्ता में आई बढ़ चली महंगाई

प्रेम कुमार
वरिष्ठ पत्रकार

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 21 मार्च को ट्वीट कर नीति आयोग के आंकड़ों के जरिए तीन प्रमुख बातों की ओर ध्यान दिलाया था। गरीबी में उत्तर प्रदेश तीन प्रमुख राज्यों में है, कुपोषण में तीसरे नंबर पर है और बाल एलवं किशोर मृत्यु दर की श्रेणी में पूरे देश में सबसे खराब हालत में उत्तर प्रदेश है।

दरअसल यही सच्चाई भी है कि चुनावों में फिर से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही महंगाई लगातार बेकाबू होती जा रही है। इससे बेपरवाह सरकार इस पर लगाम लगाने के बजाय बांटो और राज करो के अपने एजेंडे पर जुटी है।

हालात अब सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे देश के बिगड़ चुके हैं। भारत के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। भुखमरी में देश का नाम रौशन हो रहा है। आर्थिक विकास के छाती ठोंक दावों के बीच रिजर्व बैंक से लेकर आईएमएफ और विश्व बैंक तक भारत के लिए अपने अनुमानों को समेट रहे हैं। महंगाई दर बीते 17 महीनों में उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है और रोजगार खोने वालों की संख्या सिर्फ मार्च महीने में 14 लाख पार कर चुकी है।

बेबस भारत की दुर्दशा को समझने के लिए इन पांच बातों पर गौर करें-

विश्व गुरु बनने की क्षमता रखने वाला भारत भुखमरी के वैश्विक सूचकांक (GHI-2021) में 116 देशों के बीच 101वें नंबर पर लुढ़क गया है। नेपाल (76), बांग्लादेश (76), म्यांमार (71) और पाकिस्तान (92) जैसे पड़ोसी देश भारत से काफी बेहतर स्थिति में हैं।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के आर्थिक विकास वृद्धि दर का अनुमान 7.8 फीसदी से घटाकर 7.2 फीसदी कर दिया है। विश्व बैंक ने भी अपना अनुमान 8.7 फीसदी से संशोधित कर 8 फीसदी कर दिया है।

मार्च 2022 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर 6.95 प्रतिशत के स्तर पहुंच गयी जो बीते 17 महीनों में उच्चतम स्तर है।

मार्च 2022 में 14 लाख रोजगार घट गये। फरवरी 2022 में रोजगार की दर 36.7 फीसदी थी जो मार्च में घटकर 36.5 फीसदी रह गयी है।

महंगाई बेलगाम

महंगाई और बेरोजगारी ने आम लोगों का जीना मुश्किल दिया है। महंगाई बेरोकटोक बढ़ रही है। नींबू 400 रुपये किलो तक जा पहुंचा है। महंगाई सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थों की कीमतों में दिख रही है। अनाज, मांस, मछली, तेल, घी, सब्जियां, दाल, कपड़े, जूते आदि के दामों में तेज बढ़ोतरी दिख रही है। यही आम लोगों के लिए परेशानी का सबब है। जनता कराह रही है।

वार्षिक महंगाई दर मार्च 2022 में 6.95 फीसदी के स्तर पर पहुंच गई। इसने सारे

मार्च 2022
महंगाई दर मासिक परिवर्तन

सीपीआई	6.95%	1.0%
खाद्य इंडेक्स	7.68%	1.4%
अनाज	4.93%	0.8%
मीट/मछली	9.63%	5.0%
तेल, घी	18.79%	5.3%
सब्जियां	11.64%	-1.6%
दाल	2.57%	0.1%
कपड़े, जूते	9.40%	0.9%
हाऊसिंग	3.38%	-0.1%
ईंधन	7.52%	0.9%
विविध	7.02%	0.7%

अनुमानों को धराशायी कर दिया है। इससे पहले 2020 में महंगाई दर इसी स्तर पर थी। खाद्य महंगाई दर लगातार छठे महीने बढ़ती हुई 7.68 फीसदी के स्तर पर आ पहुंची है।

नवंबर 2020 के बाद यह उच्चतम स्तर है। तेल और घी की कीतमें भी 18.79 फीसदी बढ़ी है जबकि सब्जियों के भाव में 11.64 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है।

मांस-मछली 9.63 फीसदी महंगा हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए महंगाई दर का अनुमान संशोधित कर 5.3 फीसदी से 4.7 फीसदी किया है। मगर, वर्तमान में यह संशोधन भी पुनरीक्षण की मांग करता हुआ नज़र आ रहा है।

पेट्रोल-डीजल की कीमत में बढ़ोतरी भीषण गर्मी के मौसम में चढ़ते पारे जैसी खबर बन चुकी है। 'गर्मी तो झेलनी ही होगी' वाले अंदाज में महंगा पेट्रोल-डीजल तो खरीदना ही होगा।

सीएनजी, पीएनजी और घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम भी इसी अंदाज में बढ़ते चले जा रहे हैं। सबका असर ऑटो और बस किरायों से लेकर माल ढुलाई और रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों में दिख रहा है। महंगाई बढ़ने की यही मूल वजह है।

सीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी पेट्रोल-डीजल के मुकाबले भी तेज है। सिर्फ 15 दिन में लगभग 15 रुपये प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत बढ़ गीय है।

1 से 15 अप्रैल के बीच सीएनजी की कीमत 14.98 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ चुकी है। दिल्ली-एनसीआर में 15 दिनों में पांचवीं बार सीएनजी की कीमतें बढ़ाई गयी हैं।

फोटो स्रोत : गूगल

यूं महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल

तारीख	पेट्रोल	डीजल
1 मार्च	95.45रु/ली	86.71रु/ली
31 मार्च	101.85रु/ली	93.11रु/ली
16 अप्रैल	105.41रु/ली	96.71 रु/ली

फोटो स्रोत : गूगल

देशभर में बेलगाम महंगाई दर पर एक नजर

साल	महंगाई दर	वार्षिक परिवर्तन
2020	6.62%	2.90%
2019	3.72%	-0.22%
2018	3.95%	0.62%
2017	3.33%	01.62%
2016	4.95%	-0.62%
2015	4.91%	-1.74%

आमदनी घट रही है कर्ज बढ़ रहा है

भारत में प्रतिव्यक्ति आय लगातार गिर रही है और घरेलू और विदेशी कर्ज बढ़ने के कारण हरेक भारतीय पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। आज प्रति व्यक्ति आय एक लाख से कम हो चुकी है जबकि प्रति व्यक्ति कुल कर्ज 1 लाख रुपये के करीब पहुंचता दिख रहा है। वर्ष 2019-20 और 2021-22 के दौरान भारत के घरेलू और विदेशी कर्ज में 35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

ये आंकड़े इसलिए चिंताजनक हैं क्योंकि इसी अवधि में श्रीलंका पर कर्ज 33 प्रतिशत और पाकिस्तान पर 30 प्रतिशत बढ़ा है। श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों इन कर्जों की वजह से तबाह हो रहे हैं तो आशंका बन रही है कि कहीं भारत की दुर्गति भी तो उनकी ही जैसी नहीं होने वाली है!

फोटो स्रोत : गूगल

आर्थिक संकट और सामाजिक तनाव

अरुण कुमार त्रिपाठी
वरिष्ठ पत्रकार

देश में इतनी गहरी आर्थिक परेशानी के बावजूद हमारे समाज का बड़ा हिस्सा या तो अल्पसंख्यकों को खलनायक बनाने में जुट गया है या फिर उस पर सीधे हमले में शामिल हो रहा है। यह स्थिति तब पैदा होती है जब कोई समाज मानसिक असंतुलन या दृष्टिदोष का शिकार हो जाता है। आप सब्जी की दुकान से लेकर रेलवे और हवाई अड्डे तक कहीं भी चर्चा का विषय देखिए तो महंगाई और आर्थिक समस्या है ही नहीं। अगर आप महंगाई की चर्चा करेंगे तो गरीब तबका डर के मारे चुप्पी साध लेगा और पास खड़ा खाया अघाया मध्यवर्ग का व्यक्ति आपके मुंह नोच लेगा। शायद उसे लगता है कि महंगाई की आलोचना उसके नेता की आलोचना है और उसे वह कैसे बर्दाश्त करेगा।

एक ओर इस बात पर चर्चा हो रही है कि अल्पसंख्यक समाज इस स्थिति में कैसे रहे तो दूसरी ओर यह पूछा जा रहा है कि आखिर इस सामाजिक तनाव का प्रभाव क्या होगा? क्या ऐसा सहज रूप से हुआ है या फिर ऐसा बनाया गया है? कुछ तो मानव स्वभाव ऐसा होता है कि वह गरीबी और आर्थिक परेशानियों की बजाय धर्म और जाति जैसे सामाजिक मुद्दों पर ज्यादा चर्चा करता है लेकिन ऐसा नहीं होता कि समाज आर्थिक चुनौतियों को एकदम भूल जाए। घर परिवार के बजट से लेकर देश की आर्थिक स्थिति तक यह ऐसा सवाल है जो हमें छूना चाहिए और जिसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। इसकी वजह साफ है कि हमारी राजनीतिक

प्रणाली इसे मुद्दा बनने नहीं देती। वह चाहती है कि समाज निरंतर विभाजित रहे और विभाजन और ध्रुवीकरण इतना बढ़ जाए कि देश दो प्रमुख धर्मों के आधार पर बंट जाए। एक धर्म का समाज सदैव दूसरे धर्म से आतंकित रहे और ऐसा ही दूसरे समाज के साथ रहे। इस आशंका और तनाव के बीच धार्मिक आधार पर वोट बैंक बढ़ता रहे। यानी जो लोग वोट बैंक की सर्वाधिक आलोचना करते थे वे अपना वोट बैंक निरंतर बढ़ाने में लगे हैं।

अगर महंगाई के ताजा आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 17 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर पर है। वह आंकड़ा 6.9 प्रतिशत है। जबकि सकल मूल्य मुद्रास्फीति 14.55 प्रतिशत के स्तर पर है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के साथ रसोई गैस के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। मुंबई में पेट्रोल 19 अप्रैल को 120 रुपए प्रति लीटर के सबसे ऊंचे पायदान पर था। सरकार ने उत्पाद शुल्क घटाने का जो भी प्रयास किया वह अब बेअसर हो चुका है। पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों के कारण खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति मार्च के महीने में 16 माह के सबसे ऊंचे स्तर यानी 7.68 प्रतिशत के पायदान पर पहुंच चुकी है।

निश्चित तौर पर इन सारी आर्थिक स्थितियों का असर आम जनता के बजट पर तो पड़ेगा इसका देश की अर्थव्यवस्था पर घातक प्रभाव हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए का मूल्य एक डॉलर के मुकाबले 77 रुपए के करीब है। वित्त विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह गिरावट रुकने की बजाय 80 रुपए तक जा सकती है। इसी तरह कच्चे तेल की कीमत जो अभी 130 डॉलर प्रति बैरल है वह 150 तक जा सकती है। अगर कच्चे तेल का दाम 120 डॉलर प्रति बैरल रहता है तो भारत के आयात बजट पर 70 अरब डालर का अतिरिक्त दबाव पड़ता है। उधर तेल की घरेलू कीमत को संभालने के लिए सरकार उत्पाद कर में पांच से 10 रुपए प्रति लीटर की जो कटौती करती है उससे 20 अरब डॉलर का राजस्व घाटा होता है।

चूंकि भारत अपनी आवश्यकताओं का 80 प्रतिशत तेल आयात करता है इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के बढ़ने से चालू खाते का घाटा जीडीपी का 1.3 प्रतिशत हो गया है। उधर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी के 5.66 प्रतिशत से मार्च में 6.01 प्रतिशत तक चला गया है।

रूस और यूक्रेन के युद्ध के उपरांत बना यह संकट चौतरफा है। खेती के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। फास्फेट और

फोटो स्रोत : गूगल

फोटो स्रोत : गूगल

पोटेशियम उर्वरकों का संकट पैदा हो गया है। एक अप्रैल को गैर यूरिया उर्वरकों का जो भंडार उपलब्ध था उसके कारण खरीफ के फसल के समय उर्वरकों की भारी कमी होने का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच कंपनियों ने डीएपी की कीमत 24,000 से 27,000 प्रति टन कर दिया है।

मुद्रास्फीति के कारण बन रहे इस संकट को महज राष्ट्रीय नेतृत्व में आस्था जताकर कम नहीं किया जा सकता। इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ना ही है। इससे वित्तीय घाटा तो बढ़ेगा ही और आर्थिक विकास दर वह स्तर नहीं पा सकेगी जिसकी उम्मीद थी। यूनाइटेड नेशन्स कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी अंकटाड के अनुसार 2022 में भारत की विकास दर 4.6 प्रतिशत तक गिर सकती है। पहले यह दर 6.7 प्रतिशत तक रहने का अनुमान था। हालांकि रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण जो प्रतिबंध लग रहे हैं और आयात निर्यात पर तमाम तरह की बंदिशें बनी हैं उससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। अंकटाड का अनुमान है कि रूस में तो संकट आएगा ही लेकिन भारत को भी तमाम तरह के संकट का सामना करना पड़ेगा। इन संकटों में ऊर्जा का संकट, महंगाई का संकट, वित्तीय अस्थिरता का संकट शामिल है। यह सही है कि भारत में राजनीतिक स्थिरता है लेकिन वह कब तक रहेगी कहा नहीं जा सकता। आर्थिक मोर्चे पर भारत वहीं जा रहा है जहां श्रीलंका पहुंच गया है। संभव है कि भारत बड़ा देश है और वैसी स्थितियों में न जाए लेकिन उन संकटों का सामना करने के लिए जिन उपायों का सहारा लिया जा रहा है वह क्या उचित है?

सामाजिक तनाव के माध्यम से आर्थिक संकट के प्रबंधन का फार्मूला पुराना है। फासीवाद के विश्लेषण में कहा ही गया है कि वह पूंजीवाद के संकट से पैदा होने वाली प्रक्रिया है। वह अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा पर आधारित होता है। वह बहुसंख्यकों के कल्याण के नारे के साथ आता है। उसमें नस्ल, धर्म और जाति की श्रेष्ठता का भाव होता है। और अल्पसंख्यकों को हीन बताने, गद्दार बताने और गंदे बताने का आख्यान होता है। बीसवीं सदी के जर्मनी और इटली में नाजीवाद और फासीवाद के उदय को हम क्लासिक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं।

दुनिया के कई देशों में बहुसंख्यकवाद और तानाशाही सत्ताओं का दौर चल रहा है। इस समय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उसके सबसे ज्वलंत उदाहरण हैं। उन्होंने युक्रेन पर हमला करके दुनिया को नए शीत युद्ध और फिर तीसरे विश्वयुद्ध की ओर ठेल दिया है। विडंबना देखिए कि भारत जैसा अपने को शक्तिशाली बताने वाला और

विश्व गुरु होने का दावा करने वाला देश इस कृत्य की खुलेआम आलोचना भी नहीं कर पा रहा है। इस तरह अगर कल को पुतिन हट भी जाएं तो पुतिनवाद नहीं जाने वाला है। मौजूदा दौर पुतनिवाद की जीत का दौर है। भारत में पुतिन के समर्थकों की अच्छी तादाद है।

वे चाहते भी हैं कि भारत का राष्ट्रीय नेतृत्व भी पुतिन जैसा ही बने। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी वही हैं। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोजन भी वैसे ही हैं। हंगरी के राष्ट्रपति विक्टर ओरबन भी उसी किस्म के नेता हैं। ब्राजील के बोलसोनारो की भी श्रेणी वही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत यह सब लोग दुनिया से उदारवाद को खत्म करके एक आक्रामक और कट्टर राज्य की स्थापना का संकल्प रखे हुए हैं। यह अनुदार राज्य दिखाता है कि वह बहुत सशक्त है और किसी भी संकट का सामना कर सकता है। लेकिन उसकी हकीकत यह है कि वह नए नए किस्म के संकट को आमंत्रित करता रहता है। लेकिन जनता को उसका अहसास होने नहीं देना चाहता। क्योंकि वह कुछ दुश्मन अपने भीतर पाल लेता है तो कुछ दुश्मन देश के भीतर।

वह लगातार उन्हीं दुश्मनों से लड़ते रहना चाहता है।

दूर जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि अपने पड़ोस में ही इस तरह की रणनीति का शास्त्रीय उदाहरण हम देख सकते हैं। उस संकट का एक उदाहरण में हाल में पाकिस्तान में लोकतंत्र पर आए संकट के रूप में देख सकते हैं। जहां प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से हटना पड़ा लेकिन उन्होंने हटने से पहले कितना नाटक किया। उनका सारा नाटक लोकतंत्र के साथ छल करने और अपने आर्थिक कुप्रबंधन को ढकने का नाटक था। इमरान खान भी आर्थिक संकट को संभाल नहीं पा रहे थे। रोचक बात यह है कि वे इस दौरान भारत को संप्रभु बताकर उसकी तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन हकीकत कुछ और ही है जिसे हमारे मुख्यधारा के मीडिया ने दिखाया ही नहीं। वह तो इमरान खान की ओर से भारत की तारीफ ही दिखाता रहा। उसने यह नहीं बताया कि किस तरह एक संकटग्रस्त लोकतंत्र वाले देश के सुप्रीम कोर्ट ने वहां की असेंबली यानी विधायिका और जनादेश की मर्यादा को बचाया।

इसी तरह का क्लासिक उदाहरण श्रीलंका का है। वहां राजपक्षे परिवार ने सत्ता पर जिस तरह से एकाधिकार कर रखा है उसने श्रीलंका को एक नए किस्म के संकट की ओर ठेल दिया है। श्रीलंका की राजनीतिक व्यवस्था राजपक्षे के परिवारवाद की जबरदस्त गिरफ्त में है। राष्ट्रपति गोटाब्या राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे तो भाई हैं ही लेकिन उनके परिवार के तमाम लोग कैबिनेट मंत्री और दूसरे पदों पर काबिज हैं। श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट यानी श्रीलंका पोडुजना पेरामुना नाम की सत्तारूढ़ पार्टी का पूरा आधार सिंहली बहुसंख्यकवाद पर टिका है। इस बहुसंख्यकवाद के केंद्र में धर्म का फासीवाद है।

इस राष्ट्रवाद ने अपने आर्थिक आधार को मजबूत करने के लिए चीन का सहारा लिया

फोटो स्रोत : गूगल

फोटो स्रोत : गूगल

जहां किसी प्रकार के मानवाधिकार को महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन चीन ने श्रीलंका की जो मदद की उसके बदले उसे कर्ज से इतना लाद दिया कि उसका आगे चलना दुश्वार हो गया। जब श्रीलंका उर्वरकों के आयात की स्थिति में नहीं था तो उसने आर्गेनिक फार्मिंग करने को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई। नतीजतन उसका उत्पादन घट गया और खाने के लाले पड़ने लगे। आज वहां समाज के हर हिस्से के लोग मिलकर मौजूदा निजाम के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे राजपक्षे परिवार को सत्ता से हटाने की मांग कर रहे हैं और उन्हें महसूस हो रहा है कि सिंहली बहुसंख्यकवाद उनके देश के लिए कितना घातक सिद्ध हुआ है। उन्होंने बौद्ध धर्म और सिंहली बहुसंख्यकवाद के प्रभाव में यह ध्यान ही नहीं दिया कि देश की आर्थिक स्थिति कहां जा रही है।

श्रीलंका एक नमूना है भारत जैसे बड़े देश के लिए। हालांकि भारत बड़ा देश है लेकिन यह संभव नहीं है कि आर्थिक कुप्रबंधन से भारत अप्रभावित रहे। श्रीलंका से आने वाले शरणार्थियों की समस्या तो भारत को परेशान करेगी ही लेकिन नोटबंदी और जीएसटी की मार से पीड़ित भारतीय अर्थव्यवस्था भारत को सहज स्थिति में नहीं रहने देगी। भारत के शासक दल और सत्ता प्रतिष्ठान के पास कोरोना और रूस युक्रेन युद्ध की ढाल है जिससे वह अपने कुप्रबंधन को ढकने की कोशिश करेगा। लेकिन यह बहाना कब तक चलेगा कहा नहीं जा सकता। क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि ऐन कोरोना के वक्त देश में जबरदस्त किसान आंदोलन छिड़ा और सारे नकारात्मक प्रचार और बदनामी के बावजूद अपने मुकाम तक पहुंच गया।

सरकार और शासक दल सोचता है कि सामाजिक तनाव और नफरत बढ़ने से अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वह नफरत फैलाने वालों को पूरी छूट देती है। रोचक तथ्य है कि कर्नाटक में हिजाब के बहाने लंबे समय से छिड़े विवाद के कारण अब व्यापार के क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय का बायकाट शुरू हो चुका है। कर्नाटक में मार्च में हुए धार्मिक उत्सव के

मौके पर मंदिरों ने स्पष्ट तौर पर अपने परिसर में अल्पसंख्यक समुदाय को दुकानें लगाने की इजाजत नहीं दी। जबकि वहां ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है और लोग मंदिरों के प्रांगण में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग खूब दुकानें लगाया करते थे।

कर्नाटक का समाज आमतौर पर शांतिप्रिय रहा है। वहां इस तरह के बायकाट और नफरत की राजनीति नहीं होती थी और इसलिए वहां शिक्षा का प्रसार भी हुआ और आर्थिक तरक्की भी हुई। यही वजह है कि बेंगलुरु शहर आईटी का केंद्र बना। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई और उसकी पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सक्रिय हुआ तब से समाज में तनाव की जड़ें गहरी होती जा रही हैं। इसी तनाव के भय से उद्योगपति किरण शॉ मजूमदार ने सरकार को आगाह किया कि अगर ऐसा होता रहा तो उद्योग व्यापार को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन धमकाए जाने के बाद उन्होंने अपना बयान बदल लिया। हालांकि इस तरह की चेतावनी भाजपा के ही पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी दी थी।

लेकिन नफरत का यह एजेंडा सरकार के दमन तंत्र के साथ चल रहा है। रामनवमी और रमजान के मौके पर देश के आधा दर्जन राज्यों में कम से कम दर्जन भर जगहों पर हिंसा हुई या दंगे हुए। लेकिन कार्रवाई बहुसंख्यक समुदाय के उन लोगों पर नहीं हुई जिन्होंने जुलूस के दौरान मस्जिदों पर भगवा झंडे लगाए या भड़काऊ नारे लगाए। बुलडोजर उन लोगों के घरों पर चल रहे हैं जिन्होंने बाद में अपने सम्मान और धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए कोई कार्रवाई की या कुछ कहा। सबसे ताजा मामला दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का है।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय की संपत्तियों और घरों पर धुआंधार बुलडोजर चल रहा है। खरगौन में बुलडोजर उन अल्पसंख्यक घरों पर भी चला दिया गया जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनवाए गए थे। वहां के गृह मंत्री खुले शब्दों में अल्पसंख्यक समुदाय को चेतावनी दे रहे हैं कि जो पत्थर फेंकेगा उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। इस बीच मस्जिदों पर अजान के लिए लगाए गए लाउडस्पीकर को हटाए जाने का अभियान भी छेड़ दिया गया है। कहा जा रहा है कि अगर मस्जिदों से अजान पढ़ी जाएगी तो सामने ही हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक यह मामला जोर पकड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में तमाम मस्जिदों ने अपने लाउडस्पीकर का वॉल्यूम कम करना शुरू कर दिया है। चूंकि सरकार का आदेश हुआ है कि वे लाउडस्पीकर को परिसर के भीतर ही सुनने लायक वॉल्यूम पर बजाएं।

राम नवमी के दिन जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में सामिष भोजन खाने को लेकर मारपीट हुई। जेएनयू में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि खाने पीने को लेकर कोई आपत्ति हुई हो। जाहिर है कि नफरत का एजेंडा फैलाने वाले यह सोच रहे हैं कि वे इससे आर्थिक मुद्दों को ढक देंगे। या वे सोच रहे हैं कि नफरत से आर्थिक तरक्की पर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नफरत का यह जहर समाज में किसी वायरस से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। समाज में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क्षमता निरंतर कम होती जा रही है। लोग एक दूसरे पर शक करते हैं और बात बात पर हिंसा करने को आमादा रहते हैं। यह स्थितियां एक विखंडित समाज का निर्माण करती हैं और विखंडित समाज में भला व्यापार कैसे होगा और उसकी तरक्की कैसे होगी?

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

सरकारी नीतियों और फैसलों से बढ़ी महंगाई

फोटो स्रोत : गूगल

अरविन्द मोहन
लेखक, वरिष्ठ पत्रकार

एक बयान: महंगाई वैश्विक है। श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी और छोटे देशों की कौन कहे, अमेरिका और ब्रिटेन समेत सारी दुनिया परेशान है क्योंकि युक्रेन युद्ध ने तेल और गैस की ही नहीं, गेहूं और मक्का समेत पचासों चीजों की आपूर्ति और मांग की बनी बनाई शृंखला को तोड़ा है और कीमतें तेजी से बढ़ी हैं।

दूसरा बयान: महंगाई कब नहीं थी और पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी इसके लिए क्या कारण बताते थे? बल्कि आज क्या महंगाई है? महंगाई पर तो सरकारें बदली हैं। आज तो मुफ्त राशन जैसी व्यवस्था भी है, पहले क्या था? सुरजीत भल्ला जैसे अर्थशास्त्री कहते हैं कि ग़रीबी तो एक फीसदी के नीचे आ गई है।

बयान तीन: जब एक के बाद एक कोरोना और विश्वयुद्ध का खतरा आ जाए तो अकेले भारत जैसे देश की सरकार कितना कर सकती है? श्रीलंका और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो दम तोड़ती दिख रही है और सरकार ने कम नहीं किया है। युद्ध में तो हमारी इज्जत और मांग बढ़ी है।

यह सच है कि महंगाई पहली बार नहीं आई है और कोरोना तथा युक्रेन युद्ध ने परेशानियां बढाई हैं। लेकिन हमारा ही नहीं, दुनिया का रिकार्ड है कि महंगाई और मुद्रास्फीति के मामले में हर सरकार बैकफुट पर होती है क्योंकि आंख में शर्म नामक भी कोई चीज होती है। हमारी सरकार और इसके समर्थक खास हैं जो महंगाई के सवाल पर बिना पलक झपकाए सरकार को सही और महंगाई

का सवाल उठाने वाले को देशद्रोही बताने में लगे हैं।

पूरा संघ परिवार महंगाई और बेरोजगारी जैसी परेशानियों (काला धन विदेशों से वापस लाने और अच्छे दिन आने की बात तो भूल ही जाइये) से देश का ध्यान भटकाने के लिए अजान, हनुमान चालीसा, रामनवमी पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से लेकर न जाने क्या क्या कर रहे हैं। उनको माहौल बिगाड़ने और उससे पहले उसके लिए माहौल बनाने का रोजगार मिला है पर महंगाई तो उनको भी डस रही होगी। महंगाई किसी को नहीं छोड़ती और उसकी मार बहुत कड़वी होती है।

हां, यह भी सच है कि महंगाई का लाभ भी समाज का एक वर्ग उठाता है, पर इस बार की महंगाई का खास चेहरा यह है कि इसका सबसे बड़ा लाभ सरकार उठा रही है। अपने उल जलूल कार्यक्रमों और शौक पर खर्च कर रही है, अपने बचे-खुचे कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में दे रही है और कुछ मुफ्त राशन जैसी योजनाओं से 'लाभार्थी' बना रही है जिनसे नमक का कर्ज चुकाने के नाम पर वोट मांगा और पाया जा रहा है!

इस बार की महंगाई का सबसे उल्लेखनीय पक्ष यह है कि नींबू जैसे उत्पाद को छोड़कर कहीं भी मांग और आपूर्ति या मौसमी उतार-चढ़ाव का असर नहीं दिख रहा है। पूरी की पूरी महंगाई सरकारी फैसलों और नीतियों से आई है। भयावह महंगाई है। सरकारी तंत्र और लूट का डरावना जाल बुना गया है। सारे आंकड़े संदेहास्पद हो गए हैं। जिस थोक मूल्य सूचकांक पर घट-बढ़ के आधार पर महंगाई का अब तक पता चलता था उसे मोदी सरकार ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है और जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बना है उसमें हमारे, आपके उपभोग के वस्तुओं का भारांक (वेटेज) संदेहास्पद ढंग से ऊपर-नीचे किया हुआ है। सरकार ने अपने संगठन से, जो ब्रिटिश राज के समय से आंकड़े जुटाने का काम करता था, सर्वेक्षण और गणना का काम कराना बंद कर दिया है। बाकी चीजों में सरकारी आंकड़े भले ही जैसे भी हों, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़ों की वैश्विक प्रतिष्ठा रही है और लक्षित महंगाई वाली बहुत ही आधुनिक प्रणाली को पर्सी मिस्त्री, रघुराम राजन, जस्टिस श्रीकृष्ण और उर्जित पटेल की अगुवाई वाली कमेटियों ने लम्बी चर्चा और विचार विमर्श से फाइनल किया था। उसमें चार फीसदी का लक्ष्य सरकार जाने कब का भूल चुकी है और दो फीसदी प्लस-माइनस की जो भारी गुंजाइश छोड़ी गई थी, आज उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उस छह फीसदी को भी पार करके सात के करीब चला गया है।शोर मचना तभी शुरू हुआ है।

असल में जब खाने-पीने की चीजों पर महंगाई की मार हद पार कर गई तब यह शोर मचा, वरना सोने-चांदी, कपड़े और पेट्रोलियम की महंगाई तो लगातार चलती ही रही है। अकेले मार्च महीने में सूचकांक लगभग एक फीसदी(0.88 फीसदी) चढ़ गया। खाद्य पदार्थों में सबसे ज्यादा असर खाद्य तेलों और ढुलाई महंगा होने का हुआ। सरकार और उसके भक्तों के पास दन से यूक्रेन युद्ध का नाम लेने और दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का बहाना आ गया।

फोटो स्रोत : गूगल

फोटो स्रोत : गूगल

तय मानिए कि जिस तरह दुनिया में खाद्यान्न के दाम बढ़े हैं उससे हमारे यहां भी कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि सरकार अनाज बेचने के वैश्विक जुगत में लगी है।

तेलहन तथा दलहन में हम दिन ब दिन आयात पर निर्भर होते गए हैं और इस महंगाई में सरकार का दोष यह है कि उसने समय पर अपने लोगों को लाभ नहीं लेने दिया और मुद्रास्फीति की वृद्धि देखकर भी केन्द्रीय बैंक की ऋण नीति को भी ज्यादा से ज्यादा नरम रखा जिससे बाजार से भारी उधार जमा कर लेना सम्भव हो।

आज अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने सूद की दर में एक वृद्धि कर दी है और पांच और वृद्धि की तैयारी कर रहा है।

ब्रिटेन ने भी तीन बार सूद की दर बढ़ाई है लेकिन हमारा रिजर्व बैंक चार फीसदी के लक्षित मुद्रास्फीति की सीमा पार होने के बाद भी सालों से आंख बंद करके पैसा उठाए जा रहा है। उसका लक्ष्य 200 अरब डॉलर का उधार जुटाने का है। कुछ जानकार इसी चलते आज का श्रीलंका, कल का भारत जैसा जुमला कहने लगे हैं।

हम अभी इस जुमले के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा करने की वजह यह है कि महंगाई और मुद्रास्फीति की चर्चा ज्यादा जरूरी है और सरकार ने ऐसी-ऐसी गलतियां की हैं जो देश को जाने कब तक भोगनी पड़ेगी।

जब मनमोहन राज में पेट्रोलियम की कीमतें 120-125 डॉलर बैरल तक गई थीं और यहां खुदरा कीमत बढ़ी तथा सभी तरह के पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत बाजार के हवाले की गई तो इन्हीं नरेन्द्र मोदी और उनकी भक्त टोली ने बहुत शोर मचाया था और जब कीमतें बीस-पचीस डालर आ गईं तो मोदी जी उसे अपने भाग्य से जोड़ रहे थे लेकिन उनके वित्त मंत्री अरुण जेटली आम उपभोक्ताओं को लाभ देने की जगह सरकारी खजाने को भरने के लिए कर बढ़ाते गए।

आज हालत यह हैं कि हर साल ढाई से पौने तीन लाख करोड़ रुपए ज्यादा का राजस्व सरकारी खजाने में जा रहा है। यह तब भी हुआ जब तेल की कीमतें ऋणात्मक हो गई थीं। तेल का भंडारण खर्चीला और मुश्किल है और उसके उत्पादन को एकदम से बंद नहीं किया जा सकता इसलिए एक दौर में मुफ्त तेल उठाने या पैसे लेकर तेल उठाने की स्थिति आई तब भी हमारे यहां पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत आसमान पर ही रही।

उसकी गिरावट होती तो एक स्वाभाविक लाभ माल ढुलाई से लेकर खेती तक के हर क्षेत्र को होता और आम उपभोक्ता

भी लाभ पाता।

कम से कोरोना वाले दौर में तो दुनिया में यही स्थिति रही। लगभग सभी जगह मुद्रास्फीति की दर ऋणात्मक हो गई थी। जाहिर है लोगों को सामान और जरूरी सेवाओं के बदले कम पैसे खर्च करने पड़े। अपने यहां तो सबसे कठोर और गैर-जरूरी लॉकडाउन में स्थिति उल्टी हो गई थी। हर चीज महंगी हो गई, हर सेवा महंगी हो गई और जिन चीजों की कीमतें सरकार के हाथ में थीं वे सबसे खुली लूट का माध्यम बनीं।

हर हिसाब से जब एक ऊंचे आधार से महंगाई की गणना होगी तो असलियत आंकड़े से ज्यादा भयावह हैं। अगर यूरोप और अमेरिका वगैरह में मुद्रास्फीति कुछ बढ़ी है तो ऋणात्मक आधार के चलते असल में कम ही है।

इस दौर में सरकार ने दूसरी गलती या दूसरा पाप यह किया कि मुद्रास्फीति की दर तय चार फीसदी से ऊपर आने पर भी (जबकि थोक मूल्य सूचकांक तो कब से दोहरे अंकों में आकर महंगाई का शोर मचा रहा था) उसने रिजर्व बैंक के रेट में बढोतरी न करके अपना पैसा बटोरू कार्यक्रम जारी रखा जबकि करोड़ों जमाकर्ताओं की जमा पूंजी की कमाई आधी से से भी कम हो गई।

अगर समय रहते केन्द्रीय बैंकिंग व्यवस्था पहल करता तो यह नौबत न आती और उद्योग-धंधों को भी लाभ मिलता। आज भी चीन न सिर्फ विकास दर में दुनिया का अगुआ बना हुआ है बल्कि उसके यहां मुद्रास्फीति की दर डेढ़ फीसदी से नीचे है। अभी हाल तक यह दर एक फीसदी से भी नीचे थी।

महंगाई पर शोर-शराबे के बाद हाल में जब अधिकारी स्तर की बात हो रही थी तो

भारत में आर्थिक-राजनैतिक ही नहीं, चौतरफा गिरावट के बावजूद खेती-किसानी जैसे अनेक क्षेत्र हैं जो आदतन देश की अर्थव्यवस्था का आधार बने हुए हैं

एक बड़े अधिकारी ने 'लाभार्थी' शब्द के ज्यादा प्रयोग से चिढ़कर कहा कि चुनाव जिताना हमारा काम नहीं है और कल को भारत श्रीलंका की स्थिति में न पहुंचे यह देखना जरूर हमारा काम है. उनकी बातों को गंभीरता से लेने के बावजूद यह कहना जरूरी है कि श्रीलंका की या पाकिस्तान की बदहाली सिर्फ मुद्रास्फीति से नहीं आई है।

भारत में आर्थिक-राजनैतिक ही नहीं, चौतरफा गिरावट के बावजूद खेती-किसानी जैसे अनेक क्षेत्र हैं जो आदतन या मजबूरी में अपना काम अच्छे ढंग से करते आ रहे हैं। सरकार उनके साथ चाहे जैसा व्यवहार करे वे देश की अर्थव्यवस्था का आधार बने हुए हैं।

कोरोना हो या यूक्रेन युद्ध, उनके काम का नतीजा ही हमें बचा रहा है और यह मत पूछिए कि अकेले पेट्रोलियम पदार्थों से मोदी सरकार ने अब तक जो पन्द्रह लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अतिरिक्त रकम जुटाई है (और इसी चलते अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़े हैं) वे किस काम में गए? वे सिर्फ लाभार्थी बनाने में ही नहीं, भक्त बनाने के भी काम आए हैं।

आप नजर डालिए, आपको आसपास ऐसे लाभार्थी और भक्त दोनों नजर आ जाएंगे और विडम्बना देखिए कि ये लोग न सिर्फ छुट्टा होकर दंगा-फसाद करते जा रहे हैं, बल्कि महंगाई और बेरोजगारी या धर्मनिरपेक्षता जैसे सवालों पर बात करने वालों को राष्ट्रद्रोही करार देने लगे हैं। वहीं सारा का सारा विपक्ष भी शांत भाव से सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करना ही राजनीति मान रहा है।

असल में मध्य और उच्च वर्ग को महंगाई से लाभ भी मिलता है या महंगाई भत्ता बढ़ने से राहत मिलती है। लगता है कि सारे विपक्षी दल इसी मध्य और उच्च वर्ग के प्रतिनिधि बन कर रह गए हैं जो खुद को गरीब और कमजोर का प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं वे भी असली मौके पर पैसे वालों को टिकट बेचकर अपना चरित्र बदलते गए हैं।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

अंबेडकर के विचारों संग झिलमिलाए स्मृति दीप

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के आह्वान पर 14 अप्रैल 2022 को राजधानी लखनऊ में पार्टी मुख्यालय सहित प्रदेश भर में सभी जनपदों में हर शहर, जिले, कस्बे, तथा गांव में दुकानों, दफ्तरों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर शाम के समय पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131 वीं जयंती पर स्मृति दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी।

सैफई में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने स्मृति दीप जलाकर भारतरत्न डॉ भीमराव अंबेडकर को

श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्री अखिलेश यादव ने इस अवसर पर कहा कि नागरिकों को संविधान के माध्यम से समानता का अधिकार व समाज में समता का भाव लाने का जो आंदोलन बाबा साहब ने किया था उसे आज और अधिक तीव्र किये जाने की जरूरत है। उसके लिए हम सदैव प्रतिबद्ध एवं सक्रिय रहेंगे। बाबा साहब ने ऐसे समाज का सपना देखा था जिसमें भेदभाव के लिए कोई स्थान न हो।

श्री यादव ने कहा कि हमारे लिए यह गौरव का विषय है कि डॉ लोहिया और डॉ अंबेडकर कई मामलों पर एक मत थे। दोनों महान नेताओं ने राष्ट्र निर्माण का एक जैसा सपना देखा था।

प्रत्येक जनपद में कार्यक्रम के समय

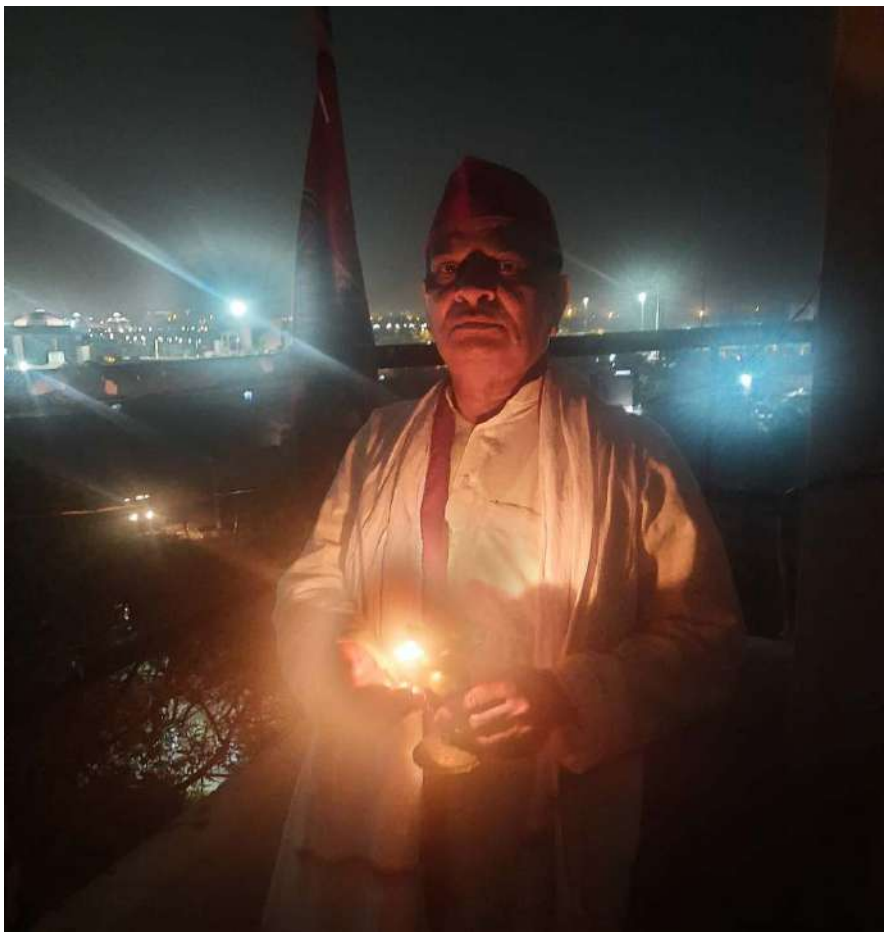

संविधान बचाने के लिए सब कुछ करेंगे समाजवादी

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि संविधान बचाने के लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा समाजवादी पार्टी वह रास्ता अपनाएगी। समाजवादी पार्टी अपना संगठन मजबूत कर जल्दी ही जनता के बीच जाएगी और जन-जागरण अभियान चलाएगी। संविधान बचाने के लिए हम लोग सब कुछ करेंगे।

श्री अखिलेश यादव 14 अप्रैल 2022 को मैनपुरी में भारतरत्न डॉ भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। श्री यादव ने कहा कि आज महंगाई से जनता परेशान है। मैंने चुनाव के समय कहा था कि चुनाव बाद भाजपा महंगाई बढ़ाएगी। आज हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। खाने-पीने से लेकर घर बनाने तक सब महंगा हो गया हैं। भाजपा सरकार महंगाई से जनता को लूट रही है। भाजपा सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। नौजवानों के लिए नौकरी रोजगार नहीं है। श्री यादव ने कहा कि भाजपा सरकार की नौकरी केवल विज्ञापन में है।

श्री यादव ने कहा कि आज हम लोग बाबा साहब को याद कर रहे हैं। हम सभी लोग संविधान बचाने के लिए आगे आएं। एक जाति दूसरी जाति का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि चुनाव में समाजवादी पार्टी को हर वर्ग का वोट मिला। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत हैं।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि देश को संविधान देते हुए बाबा साहब ने उम्मीद की थी कि अब एक व्यक्ति एक वोट से देश में असमानता की समाप्ति होगी और संविधान की प्रस्तावना के अनुकूल सुशासन व्यवस्था स्थापित होगी। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार के समय देश में गैरबराबरी बढ़ी है और दलितों, वंचितों के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं। समाजवादी अंबेडकरवादियों के साथ मिलकर प्रदेश की प्रगति तथा नए समाज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।

कार्यकर्ताओं के सामने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़कर सुनाई गई तथा इस अवसर पर भारतीय संविधान को बचाने की शपथ भी ली गई।

इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों, नेताओं तथा विधायकों ने अपने इलाके में मेधावी दलित छात्र के घर जाकर उसे सम्मानित करते हुए उन्हें पुस्तक, गमछा एवं पुष्प आदि भेंट किए। उधर समाजवादी पार्टी मुख्यालय लखनऊ में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर डॉ अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन संघर्ष को याद किया गया। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भारत रत्न डॉ अंबेडकर की 131वीं जयंती मनायी गयी।

डॉ अंबेडकर जयंती समारोह की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल और संचालन बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मिठाई लाल भारती ने किया। श्री राजेन्द्र चौधरी ने संविधान की प्रस्तावना का संकल्प दिलाया।

कार्यक्रम को सर्वश्री पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, प्रदेश उपाध्यक्ष जय शंकर पाण्डेय, पूर्व मंत्री के.के. गौतम एवं आर.के. चौधरी, एमएलसी डॉ राजपाल कश्यप ने प्रमुख रूप से संबोधित किया।

वक्ताओं ने इस अवसर पर कहा कि आरएसएस गैर-बराबरी का समाज बनाती है। भाजपा उसी एजेण्डा को लेकर चलती है। वह उन्मादी समाज का निर्माण कर रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की रक्षा के लिए समाजवादी संघर्ष जारी रखेंगे।

वक्ताओं ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार ने संविधान की मूलभूत संरचना के साथ अपने हर फैसले में खिलवाड़ किया है। बाबा साहेब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। आज के हालातों से डरने वालों को बाबा साहब का संघर्ष याद करना चाहिए, इससे जरूर रास्ता मिलेगा और परिवर्तन होगा। बाबा साहब का संविधान न होता तो गरीब का बेटा कभी बड़े पदों तक नहीं पहुंच पाता।

.... और जगमगा उठे स्मृति दीप

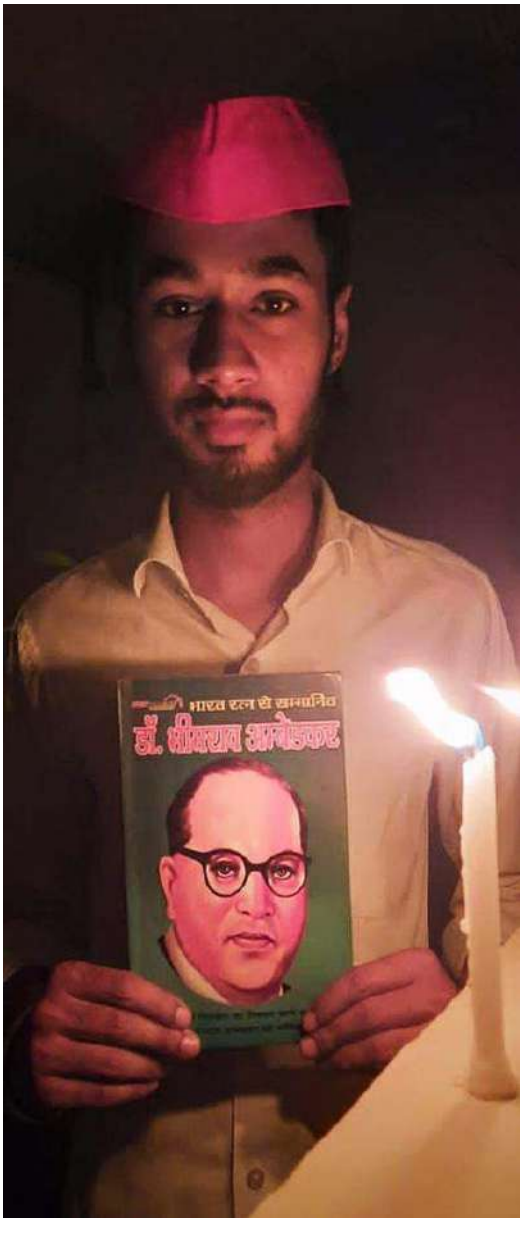
भारत रत्न से सम्मानित
डॉ. भीमराव आंबेडकर

समाजवादी पार्टी
जनपद बाँदा
SAMAJWADI PARTY

भारत रत्न

कार्यालय
समाजवादी पार्टी
जनपद - महोबा

समाजवादियों से ही है न्याय की आस

उत्तर प्रदेश में सरकार भले ही भाजपा ने बनाई हो लेकिन समाज में न्याय की आस लगाए बैठा हर तबका समाजवादी पार्टी पर ही भरोसा जता रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव के नतीजे आने के एक महीने बाद ही कई ऐसे पीड़ित लोग न्याय की आस लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से मिले। श्री अखिलेश यादव ने सबसे मुलाकात कर उनकी बातें सुनीं एवं न्याय के लिए संघर्ष करने का आश्वासन दिया।

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से दिनांक 7 अप्रैल को समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में मुलाकात कर सरकारी भर्तियों से वंचित हजारों अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मण्डलों ने ज्ञापन सौंप कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। अभ्यर्थियों की मांग है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। तमाम अभ्यर्थियों ने कहा कि वे ओवर एज होने जा रहे हैं। समय से परीक्षाएं न होने से उनका भविष्य बिगड़ जाएगा।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि अभ्यर्थियों के साथ भाजपा सरकार का संवेदनशून्य व्यवहार अनुचित और अमानवीय है। नौजवानों के सब्र का इम्तिहान नहीं लिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी नौजवानों की समस्याओं के समाधान के लिए सदन से सड़क तक आवाज उठाएगी। अधूरी भर्तियों को पूरा कराने के लिए संघर्ष होगा।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्तर पर लम्बे समय से 10 भर्तियां लम्बित हैं। 34

लाख से अधिक अभ्यर्थियों का भाग्य इनसे जुड़ा है। इनमें सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन भर्ती प्रक्रिया 2016 से अधूरी है। वर्ष 2018 से 1.19 लाख अभ्यर्थी अवर अभियंता भर्ती परीक्षा होने का इंतजार कर रहे हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण परिवेश की परीक्षाओं का विज्ञापन 2018 में जारी हुआ था।

उसकी परीक्षाएं भी हुई किन्तु बाद में किन्हीं कारणों से परीक्षाएं रद्द हो गई जो अभी तक नहीं हुई। इनमें 1 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। जब लम्बे समय से भर्ती परीक्षा लंबित है तब मुख्यमंत्री जी के 100 दिन में 20 हजार सरकारी नौकरी और 50 हजार रोजगार देने का वादा कैसे पूरा होगा? सहज ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है।

तमाम अभ्यर्थी नौजवानों ने बताया कि 32 हजार अनुदेशकों को अभी तक रोटी-रोजी से वंचित रखा गया है।

वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक भर्ती तथा मंडी परिषद की परीक्षाओं का भी कोई पुरसाहाल नहीं है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 09 (02) 2016 आबकारी पुलिस भर्ती में पक्षपात और अनियमितता बरती जाने से तमाम अभ्यर्थी अंतिम परीक्षा में बाहर हो गए हैं। शारीरिक परीक्षा और साक्षात्कार में मानक बदले गए।

सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी की परीक्षा के विज्ञापन 2019 में जारी हुए थे। इनकी परीक्षाओं की तिथि 3 बार घोषित हुई और तीनों बार स्थगित कर आज तक परीक्षा तिथि नहीं घोषित हुई। इन परीक्षाओं के लिए 904 पदों के सापेक्ष 10144 फार्म पड़े हैं।

रायबरेली का पीड़ित परिवार मिला

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से 19 अप्रैल को पार्टी मुख्यालय लखनऊ में रायबरेली के श्री विपुल पासी पुत्र स्वर्गीय दीपक कुमार पासी निवासी ग्राम जगतपुर ने परिवार सहित मिलकर क्षेत्र के दबंगों द्वारा उसे अगवाकर तथा उससे अपने पैर चटवाने जैसे अमानवीय कृत्य के लिए मजबूर करने की पीड़ा बताई।

श्री अखिलेश यादव ने पीड़ित के प्रति सहानुभूति जताते हुए उसे न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि

समाजवादी पार्टी उन वंचितों के साथ खड़ी है जिन पर सत्ता अत्याचार कर रही है।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्री आर. के. चौधरी, श्री ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री मनोज पाण्डेय विधायक, समाजवादी पार्टी रायबरेली के जिलाध्यक्ष इं0 वीरेन्द्र यादव तथा जिला सचिव एवं राष्ट्रीय पासी सेना के अध्यक्ष श्री संजय पासी भी मौजूद थे।

पीड़ित श्री विपुल पासी ने बताया कि 10 अप्रैल 2022 को गांव का ही एक व्यक्ति उन्हें बुलाकर ले गया जहां कुछ लोग उसे अपनी गाड़ी में जबरन बिठाकर घर से 5 किलोमीटर दूर जंगल में ले गए। अवैध तमंचा लगाकर उसे गोली मारने की धमकी दी। आरोपी उत्तम सिंह ने उसको अपने पैर चाटने के लिए मजबूर किया और कहा कि तुम्हारे बाप दादा भी गुलाम थे। पैर चाटने पर विपुल की जान बची। आरोपित ने इसका वीडियो भी खुद बनाया।

इस घटना के बाद भी जगतपुर थाने की पुलिस पीड़ित पर समझौता करने का दबाव बना रही थी।

लेकिन जब स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव और बड़ा प्रदर्शन किया तब 5 लोगों की गिरफ्तारी के साथ नाबालिग लड़के की तरफ से हल्की धाराओं में एफआईआर लिखी गई। उसमें भी मुख्य आरोपित को बचा लिया गया। वह अभी तक फरार है।

पीड़ित पक्ष द्वारा आरोपित के घर पर बुलडोजर चलाने, सुरक्षा एवं मुआवजा दिए जाने तथा केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश दिलाने की मांग की गई है।

बैंक लॉकर कांड के प्रभावित लोग मिले

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से 19 अप्रैल को पार्टी मुख्यालय में कानपुर के सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया व बैंक ऑफ इण्डिया की कराचीखाना शाखा में लॉकर चोरी के पीड़ितों ने मुलाकात की।

पीड़ितों ने श्री अखिलेश यादव से चोरी गए सामान और न्याय दिलाने के लिए मदद मांगी। श्री अखिलेश यादव से मिलने वाले पीड़ितों में निर्मला तहिलयानी, मीना यादव, सुशीला शर्मा, महेन्द्र सविता ने कहा कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया व बैंक ऑफ इण्डिया की कराचीखाना शाखा कानपुर के अधिकारियों ने गिरोह बनाकर लॉकरों से माल गायब कर दिया गया। बैंक के उच्च

अधिकारी पीड़ितों की शिकायत नकारते रहे कि कुछ नहीं हुआ जबकि बैंक के 11 लॉकर टूटे थे।

पीड़ितों ने श्री अखिलेश यादव से इस मामले को प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के समक्ष उठाकर नुकसान की भरपाई बैंक से करवाने में मदद मांगी। साथ ही प्रदेश सरकार से पीड़ितों को उचित मुआवजा दिलवाने की भी मांग की।

श्री अखिलेश यादव ने पीड़ितों को मदद का आश्वासन देते हुए वित्त मंत्री भारत सरकार को पीड़ितों का सामान उक्त बैंक से वापस दिलाने और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा।प्रभावित लोग श्री अखिलेश यादव के आश्वाशन से सन्तुष्ट हुए और कहा कि उन्हें अब न्याय मिलने का पूरा भरोसा है

शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी मिले

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से 18 अप्रैल को सहायक शिक्षक भर्ती में 6800 चयनित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर अपनी नियुक्ति न होने की शिकायत का ज्ञापन सौंपा।

इनका कहना है कि वंचित वर्ग के अभ्यर्थी 2 साल से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। चयनित अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमण्डल ने बताया कि सभी अभ्यर्थी पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग से आते हैं लेकिन तमाम प्रतिवेदनों के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है।

श्री अखिलेश यादव ने उनकी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुना और उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।

ज्ञापन में कहा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा 69000 शिक्षक भर्ती का आयोजन 2018 में किया गया था।

इसमें आरक्षण की विसंगतियां पाए जाने पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया गया।

बेसिक शिक्षा विभाग ने लगभग 6800 अभ्यर्थियों की नई सूची जारी की लेकिन कई माह बीत जाने के बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं हुई है।

स्वास्थ्य कर्मी

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से 18 अप्रैल को स्वास्थ्य कर्मियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर उन्हें अचानक नौकरी से हटाए जाने

की जानकारी देते हुए सेवा में पुनः बहाली की मांग का ज्ञापन सौंपा।

सेवा से वंचित स्वास्थ्य कर्मियों ने ज्ञापन में कहा है कि विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में 30 हजार स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की समय सीमा मार्च 2020 से 5 मार्च 2022 तक बढ़ाई गई थी।

गत 5 मार्च 2022 को उनकी सेवाएं बिना नोटिस दिए अचानक स्थाई रूप से समाप्त कर दी गई। 5 मार्च 2022 से सभी स्वास्थ्यकर्मी बेरोजगारी में भुखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं।

ज्ञापन में मांग की गई है कि इन स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं पुनः बहाल की जाए जब तक कि उनकी उम्र 60 वर्ष न हो जाए।

वेटनरी छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मिला

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से 13 अप्रैल को सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मेरठ, पंडित दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान मथुरा एवं आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालयों के छात्रों ने भेंट कर इंटर्न डाक्टरों का इंटनर्शिप भत्ता बढ़ाने के लिए सहयोग की मांग की।

पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने वेटनरी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में वेटनरी इंटर्न कर रहे छात्रों के लिए प्रतिमाह 30 हजार रुपये इंटर्नशिप भत्ता दिलाने के पक्ष में है। इन छात्रों की न्यायोचित मांगे तत्काल स्वीकार की जाए।श्री यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार को गौ-संरक्षण केन्द्रों के लिए पशु चिकित्सा स्नातक छात्रों को जिम्मेदारी देकर उनकी बेरोजगारी दूर करनी चाहिए।

विधानपरिषद चुनाव 2022

सत्ता के दम पर वोट की लूट

फोटो स्रोत : गूगल

बुलेटिन ब्यूरो

विधानपरिषद के स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र के चुनावों में जिस तरह सत्ता का बेजा इस्तेमाल हुआ उसने फिर एक बार साबित कर दिया कि भाजपा लोकतंत्र की सीरियल किलर है। लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जाता है, भाजपा उसकी एक्सपर्ट पार्टी बन गई है।

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन 2022 में डबल इंजन सरकार ने सत्ता के दुरुपयोग के सभी रिकार्ड तोड़ दिए। चुनाव में भाजपा की मनमानी और धांधली की सभी हदें पार हो गई। भाजपा ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है उसके लिए भाजपा को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा

दूसरों को जातिवादी बताने वाली भाजपा की ये सच्चाई है कि एमएलसी चुनाव की 36 सीटों में से कुल 18 पर मुख्यमंत्री के स्वजातीय जीते हैं। एस.सी.-एस.टी., ओबीसी को दरकिनार कर ये कैसा 'सबका साथ, सबका विकास' ?

भाजपा को संविधान, लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की प्रक्रिया में जरा भी विश्वास नहीं है। वह धन-बल और छल से

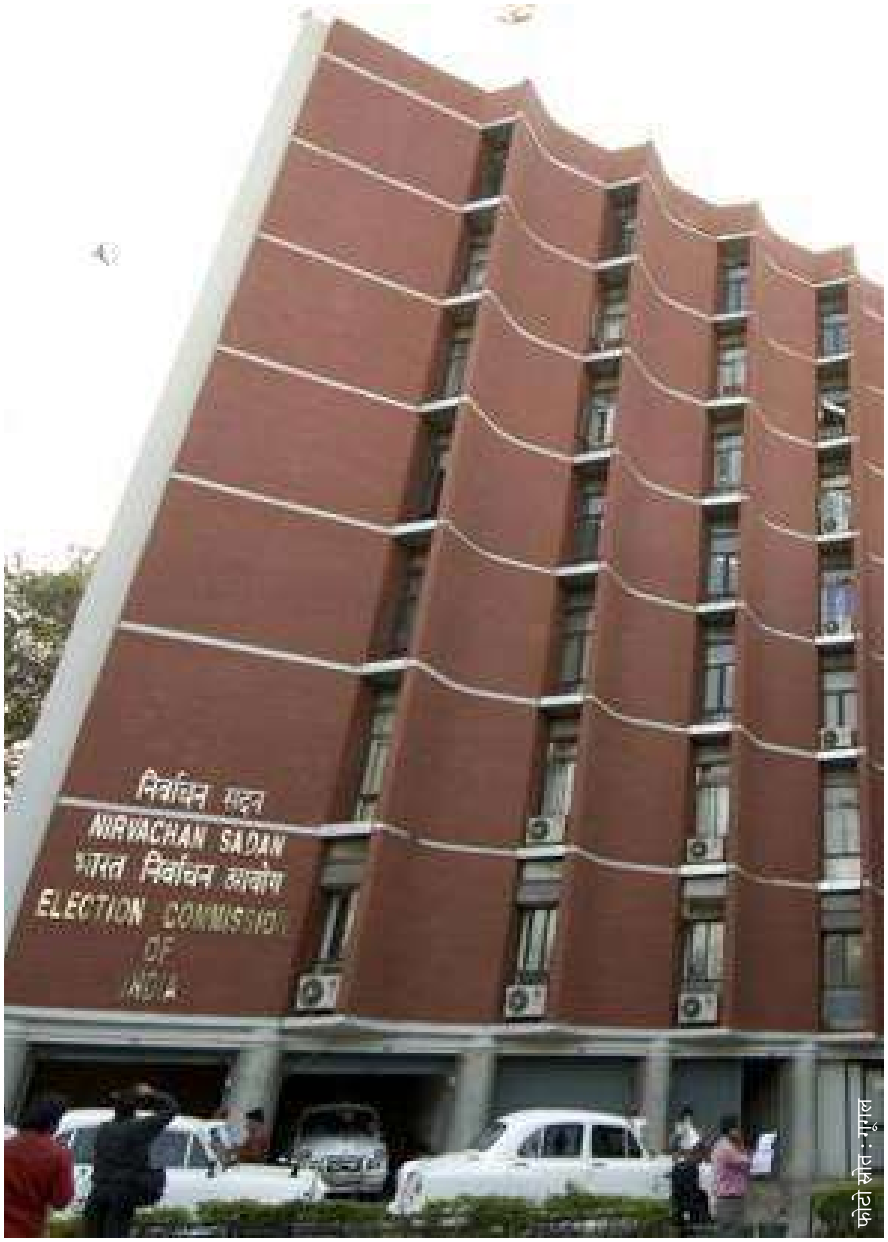

फोटो साभार : गूगल

येन-केन-प्रकारेण सत्ता में बने रहने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के साथ ही लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं को भी तार-तार करने में लगी है। पंचायत चुनावों के बाद, आम विधान सभा चुनाव 2022 और अब स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनाव में भाजपा ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कुचलने का ही काम किया है।

9 अप्रैल को हुए मतदान में बीडीसी, प्रधान, जिला पंचायत सदस्यों को मतदान करने से जगह-जगह रोका गया। सत्ता संरक्षित भाजपा के दबंग लोगों एवं सरकारी तंत्र द्वारा विभिन्न मतदान केन्द्रों पर बूथ कैप्चरिंग करने, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए मतदाताओं को धमकाने जैसी गम्भीर शिकायतें मिलीं। बड़े स्तर पर धांधली कराके धन-बल-छल से चुनाव जीतने की भाजपा की साजिशों के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पहले से बता दिया गया था फिर भी कठोर कार्रवाई नहीं होने से निर्वाचन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए।

भाजपा के पोलिंग एजेण्ट मतदान केन्द्र में बैठकर जबरन वोट दिखाकर डालने का दबाव बनाते रहे। भाजपा के लोग फर्जी मतदान कराते रहे। प्रशासन पूरी तरह से मूकदर्शक बना रहा। कई स्थानों पर प्रशासनिक अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी का एजेंट तक नहीं बैठने दिया। खुले आम क्षेत्र पंचायत सदस्यों व ग्राम प्रधानों को जबरन थानों में बैठाकर प्रताड़ित किया गया।

भाजपा सरकार और प्रशासन की मिलीभगत से विधान परिषद चुनाव में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं पूरी तरह ध्वस्त हुई हैं जो एक गम्भीर मामला है। भाजपा ने लोकतंत्र को सत्ता के डबल इंजन से कुचलने का काम किया है। भाजपा ने विधान परिषद में जबरन बहुमत पाने के लिए सभी नैतिक एवं लोकतांत्रिक मान्यताओं को ताक पर रख दिया। प्रशासन का राजनीतिक स्वार्थ में दुरूपयोग निष्पक्ष-स्वतंत्र चुनाव को भी न केवल संकट में डाल देगा अपितु उसकी विश्वसनीयता पर भी निर्मम प्रहार करेगा।

ज्योतिबा फुले के रास्ते पर चलने का संकल्प

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, विचारक, दार्शनिक और लेखक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया।

श्री यादव ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने ऐसे समय में बाल-विवाह, विधवा विवाह तथा कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जब समाज रूढ़िवादिता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। 1848 में उन्होंने देश के पहले बालिका स्कूल की स्थापना की थी। उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले देश की पहली महिला शिक्षिका बनीं। श्री यादव ने ज्योतिबा फुले के रास्ते पर चलने का संकल्प दोहराया।

जयंती कार्यक्रम में सर्वश्री राजेन्द्र चौधरी, नरेश उत्तम पटेल, संजय गर्ग, अरविन्द कुमार सिंह, सुरेश यादव विधायक, डॉ राज बर्धन जाटव सहित अन्य प्रमुख लोग उपस्थित रहे।

निषादराज का जीवन
प्रेरणास्रोत

बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर दिनांक 5 अप्रैल को राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के सभी जनपदों के पार्टी कार्यालयों में महर्षि कश्यप और निषादराज गुह्य की जयंती सादगी से मनाई गई।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने सप्तऋषियों में प्रथम महर्षि कश्यप और श्रृंगवेरपुर के महाराजा निषादराज गुह्य को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए कहा कि उनसे हमें जीवन में आगे बढ़ने और लोक कल्याण के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणास्रोत है।

श्री यादव ने कहा महर्षि कश्यप को सृष्टि सर्जक कहा जाता है। उन्होंने कई स्मृति ग्रंथों की रचना की थी। वनवास काल में राम-लक्ष्मण सीता को अपनी नौका से निषादराज गुह्य ने गंगा पार कराया था।

लखनऊ में बालागंज चौराहा हरदोई रोड स्थित निषादराज गुह्य की प्रतिमा पर समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष तथा एमएलसी डॉ राजपाल कश्यप ने माल्यार्पण कर नमन किया।

इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी हुआ। उपस्थित जनसमुदाय के बीच मिष्ठान्न वितरण भी किया गया।

याद किए गए अनंतराम जायसवाल

बुलेटिन ब्यूरो

बाराबंकी के वरिष्ठ समाजवादी नेता एवं पूर्व मंत्री श्री अनंतराम जायसवाल की 98वीं जयंती दिनांक 1 अप्रैल को समाजवादी पार्टी मुख्यालय, लखनऊ में सादगी से मनाई गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने स्वर्गीय जायसवाल के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि स्वर्गीय जायसवाल ने सांसद, विधायक तथा मंत्री पदों पर रहते हुए गरीबों, किसानों और पिछड़ों की आवाज उठाई तथा उनके लिए संघर्ष किया। वे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के पुराने नेताओं की कतार में थे। समाजवादी आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रहती थी।

इस अवसर पर स्वर्गीय जायसवाल जी के प्रपौत्र श्री दर्श जायसवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री राजेन्द्र चौधरी तथा श्री अरविन्द कुमार सिंह एम.एल.सी. ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए।

साफ़ और बेबाक

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

Socialist Leader of India. Chief Minister of UP (2012 - 2017)

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

युद्धग्रस्त यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई बीच में छोड़कर आए हुए स्टूडेंट्स की इस माँग को सरकार तुरंत माने कि उन्हें यहाँ के मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिकल क्लासेज़ करने की अनुमति दी जाए, बाक़ी पढ़ाई वे ऑनलाइन कर लेंगे।

40 मेडिकल कॉलेज का दावा करनेवाले, युवाओं के भविष्य की रक्षा करें।

Translate Tweet

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

जनता पूछ रही है कि प्रदेश भर में भाजपा से संबद्ध लोगों के अनगिनत अवैध निर्माणों पर बुलडोज़र क्यों नहीं चल रहा है।

सवाल ये है कि अवैध निर्माणकर्ता भाजपाइयों को कौन बचा रहा है और किसलिए बचा रहा है।

वैध-अवैध के नियम क्या दल देखकर लगाए जाएंगे?

Translate Tweet

लखनऊ

विधायक के पहुंचते ही थमा बुलडोजर

जानकीपुरम विस्तार में नहर रोड पर अवैध तरीके से बन रही इमारत गिराने पहुंचा प्रवर्तन दस्ता बैरंग लौटा

बिना नक्शा बन रही इमारत बीजेपी कार्यकर्ता की होने की जानकारी के बाद एलडीए टीम ने रोका अभियान

अवैध निर्माण रोकने में फेल 10 इंजिनियर प्रवर्तन टीम से हटाए गए

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

भाजपा 2.0 के राज में ~ यूपी डूबा अपराध में

आज का अपराधनामा

Translate Tweet

प्रयागराज में फिर सामूहिक हत्या:
एक परिवार के 5 का गला रेता, 4 की मौत, शवों को जलाने के लिए घर में लगा दी आग

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

भाजपा ने बुलडोज़र को अपनी ग़ैरक़ानूनी ताक़त दिखाने का प्रतीक बना लिया है। मुसलमान व अन्य अल्पसंख्यक, पिछड़े व दलित इनके निशाने पर हैं। अब तो इनके उन्माद का शिकार हिंदू भी हो रहे हैं। भाजपा दरअसल संविधान पर ही ये बुलडोज़र चला रही है।

भाजपा बुलडोजर को ही अपना प्रतीक चिन्ह बना ले।

Translate Tweet

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

आज इफ़्तार कार्यक्रम में।

Translate Tweet

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

बुलडोज़र को लेकर देशभर में आक्रोश पैदा हो रहा है। भाजपाई ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से अपने विरोधियों के निर्माण को अवैध घोषित कर बुलडोज़र चलवा रहे हैं।

अब जनता भाजपाइयों के घरों, कार्यालयों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण की वैधता की जाँच का आंदोलन छेड़ेगी और सच सबके सामने लाएगी।

Translate Tweet

Akhilesh Yadav
@yadavakhilesh

उप्र के स्वास्थ्य मंत्री जी ने जब स्वयं कह दिया है कि स्वास्थ्य विभाग व अस्पतालों की वर्तमान हालत देखकर वो शर्मिंदा हैं तो और क्या कहना। ये एक अच्छी बात है क्योंकि सत्य को स्वीकार करने से ही सुधार का मार्ग निकलता है।

एक सलाह : वो आलोचना पर FIR करनेवालों व बुलडोज़र से बचकर रहें।

Following

Akhilesh Yadav ✓
@yadavakhilesh

सत्ताधारी राजनीतिक दल जब अपराधियों का सरंक्षक बन जाए तो किसान, मज़दूर, गरीब और बाकी सारे जनमानस को न्यायालय ही हताशा से बचाता है।

न्यायपूर्ण निर्णयों से न्याय का मान भी बढ़ता है और न्याय में विश्वास भी।

'लखीमपुर' न्याय का प्रतीक बनकर इतिहास में दर्ज होना चाहिए; अन्याय का नहीं!

Akhilesh Yadav ✓ @yadavakhil... · 09 Apr

ईंधन के बेतहाशा बढ़ते दामों पर जब न कोई सरकारी नियंत्रण, न शासन, न प्रशासन, न प्रबंधन, न ही नियमन है और अगर सब कुछ बाज़ार के हवाले ही है तो फिर पेट्रोल, डीज़ल, गैस का मंत्रालय किसलिए। इस मंत्रालय को तत्काल भंग कर देना चाहिए!

भाजपाई-महंगाई जनता को निरंतर ईंधन से निर्धन कर रही है।

Akhilesh Yadav ✓
@yadavakhilesh

उप्र के मुख्यमंत्री जी से उप्र की जनता की ये अपेक्षा है कि जो लोग संतों का चोगा पहनकर, साधु-संतों का नाम बदनाम कर रहे हैं व इसकी आड़ में अपने आपराधिक कुकृत्य और ज़मीन हड़पने के अवैध कारनामों पर पर्दा डाल रहे हैं, ऐसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़नेवाले तत्वों पर तुरंत कार्रवाई करें।

Translate Tweet

Akhilesh Yadav ✓
@yadavakhilesh

भाजपा की आरक्षण विरोधी सोच और नीति का स्वयं भंडाफोड़ करते हैं ये सरकारी तथ्य:

-अधिकतम आरक्षित पद रिक्त
-विभिन्न विभागों में पदोन्नति में आरक्षण के आँकड़ों का अपर्याप्त संकलन
-ग्रुप ए से सी तक आरक्षित पदों में भी निर्धारित से कम नियुक्ति
-उच्च पदों पर नाममात्र का प्रतिनिधित्व

Akhilesh Yadav ✓
@yadavakhilesh

ये बड़ी सोच, बड़े काम का बड़ा अंजाम है
आज चंबल का बीहड़ 'शेरों' से आबाद है

Translate Tweet

Akhilesh Yadav ✓
@yadavakhilesh

आज जनता व समाज से माँ गंगा की स्वच्छता की अपेक्षा करनेवाली भाजपा सरकार बताए कि उसने अब तक क्या किया है व पिछले आठ वर्षों में अरबों का फंड किस महासागर में जा मिला है।

गंगा माँ की निर्मलता का दावा करनेवाले ये बात हाथ में गंगाजल लेकर कहें तो सबको इनके असत्य की पराकाष्ठा का पता चले।

Translate Tweet

Akhilesh Yadav ✓
@yadavakhilesh

श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि।
बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि।।

श्री हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं

Akhilesh Yadav ✓
@yadavakhilesh

आज करहल का दौरा।

Translate Tweet

Akhilesh Yadav ✓ @yadavakhil... · 09 Apr

बड़ा अच्छा लगता है उसका साया
जो पेड़ कभी हमने ख़ुद था लगाया

पंजीकृत डाक पंजीकरण संख्या GPO/LW/NP-300/2021-2023 कुल पृष्ठ : 48 डिस्पैच तिथि : 15, 16, 17

"

समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध,
जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनके भी अपराध।

- रामधारी सिंह दिनकर